यह वक्तव्य को जारी करने की पहल सन्हति ने की है। सन्हति (www.sanhati.com) शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न संघटनों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का एक समूह है। यह वेब ग्रुप भारत के जनांदोलनों के बारे में जानकारी और प्रतिक्रियाएं लोगों तक अपनी वेबसाइट द्वारा पहुंचाता रहा है।

माननीय डॉ. मनमोहन सिंह ,
प्रधान मंत्री, भारत सरकार,
साउथ ब्लाक, रायसीना हिल,
नई दिल्ली, भारत, ११००११

यह अपील भारत सरकार के प्रस्तावित नक्सल-विरोधी सैन्य अभियान के सन्दर्भ में ज़ारी की जा रही है ।

भारत के पिछड़े और आदिवासी-बहुल इलाकों- छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओड़िसा और पश्चिम बंगाल- में छेड़ा जानेवाला यह कथित अभियान हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है।

इस प्रस्तावित सैन्य कारवाई के जरिये भारत सरकार कथित रूप से इन इलाकों को माओवादियों से मुक्त करना चाहती है। लेकिन इस अभियान के चलते गरीब और भी बेघरबार होंगे और अपने रोज़ी रोटी के सीमित साधनों से हाथ धो बैठेंगे। माओवादियों का सफाया करने की आड़ में राजनैतिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों पर यह हमला न सिर्फ़ निंदनीय है बल्कि समस्या जनक भी है। इस सन्दर्भ में गौरतलब बात यह है की पिछले कुछ वर्षों से सलवा जुडुम जैसे निजी सेनाओं के साथ मिलकर पुलिस तथा सुरक्षा बलों ने पहले से ही छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में हाहाकार रचा रखा है। इस तरह की हथियारबंद लडाइयों में अब तक सैकड़ों ने अपनी जाने गवाई है और हजारों बेघरबार हुए हैं। ऐसे में यहाँ प्रस्तावित सैन्य कारवाई समस्या को सिर्फ़ और जटिल ही बनाएगी। इसके चलते आदिवासियों और गरीब किसानों को भुखमरी, बेदखली और बेईज्ज़ती के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।

सदियों से बदहाल भारतीय आदिवासीयों की स्थिति 1990 के दशक़ से चालू हुई आर्थिक नीतियों के चलते और भी बदतर हो गई है। विशेष आर्थिक झोन और आद्योगिक विकास को बढावा देने के

नाम पर सरकार ने इन क्षेत्रों की जनता से जल-जंगल-ज़मीन पर उनके रहे सहे अधिकार भी छीन लिए हैं।

खनिज पदार्थों से भरे हुए इन आदिवासी क्षेत्रों पर औद्योगिक घरानों और कारपोरेशनों की नज़रें काफ़ी दिनों से लगी हुई हैं। मल्टीनैशनल कंपनियों और भारतीय औद्योगिक घराने इन क्षेत्रों में अपना बेरोक-टोक विस्तार चाहते हैं ।

इन प्रस्तावित 'विकास' कार्यकर्मों के चलते इस क्षेत्रों की जनता को भयंकर विस्थापन और बदहाली झेलनी पड़ेगी। इस संभावना के चलते इन क्षेत्रों की जनता ने 'विकास' के इन प्रयासों का जबरदस्त विरोध किया है और कई जगहों पर तो औद्योगिक घरानों और सरकार को मुंहकी खानी पड़ी है। आज सरकार इन्ही क्षेत्रों और एक अविश्वस्नीय स्तर का सैन्य अभियान छेड़ने जा रही है। हमें संदेह है की नक्सल विरोध की आड़ में सरकार असल में इन क्षेत्रों के आंदोलनों का गला घोटना चाहती है। जन विरोध को ख़त्म करके यह सरकार बड़ी कंपनियों को प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय श्रम के शोषण की मनमानी छूट देना चाहती है। कारपोरेट पूंजी के साथ सरकारी ताल की इस मिलीभगत के चलते गरीबी और बेदखली का जो कुचक्र चल निकला है वही आज जनांदोलनों और राजनैतिक हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इस समस्या के जड़ को समझने के बजाय सरकार सैन्य अभियान की तैयारी कर रही है। गरीबी के बजाय गरीबों का सफाया करना ही आज भारत सरकार की नीति है।

हमारा दृढ़ विश्वास है की अपनी ही जनता पर इस तरह की सैन्य कारवाई भारतीय तंत्र के लिए शर्मनाक है। दुनिया के तमाम हिस्सों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों मे जब-जब राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं को सैन्य बल से दबाने की कोशिश हुई है तब तब बर्बादी और बदहाली बढ़ी है। सरकार का यह प्रस्तावित नया अभियान किसी भी समस्या का निदान कर पायेगा इसका हमें गहरा संदेह है। इसलिए हम भारत सरकार से यह अपील करते हैं कि वह अपने जनता पर हमले के इस प्रस्ताव को तुरंत स्थगित करे। इस सैन्य करवाई के चलते भारत के अन्दर एक ऐसा युद्ध शुरू हो जाएगा जिसका फायदा सिर्फ़ उन पूंजीपतियों और कारपोरेशन घरानों को मिलेगा जो प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित इस्तेमाल करना चाहते हैं। जनता के कमज़ोर वर्गों के हाथ भुखमरी और विस्थापन के अलावा कुछ और नही आएगा। हम सभी जनतांत्रिक सोच वाले लोगों का आह्वान करते हैं कि वे भारत सरकार की इस कार्यवाई का
विरोध करें और इस अपील में हमारा साथ दें।